क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 300, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

न्यूज

वायु सेना का प्रशिक्षु विमान 'किरण' दुर्घटनाग्रस्त

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वायु सेना का एक ट्रेनर विमान किरण गुरुवार को हैदराबाद के हाकिमपेट वायु सेना स्टेशन के निकट यादगिरिगट क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से विमान को उड़ा रहा प्रशिक्षु पायलट समय रहते पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। वायु सेना के प्रवक्ता के अनुसार विमान नियमित उड़ान पर था लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए 'कोर्ट आफ इंक्वायरी' का गठन किया गया है। विमान के खुले क्षेत्र में गिरने के कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

बाल मजदूरी रोधक कानून सख्ती से लागू करने के निर्देश

जालन्धर,(एजेंसी)। जिला उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने बुधवार को बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ बने कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।श्री शर्मा ने कहा कि बाल मजदूर रोधक कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और लोगों को इस कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरुक किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि पुलिस, श्रमिक, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभागों की स्पेशल टीमों का गठन कर बाल मजदूरी और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस बीमारी को मूल से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

कांग्रेस ने आतंकवाद और नक्सलवाद फैलाया: योगी

उदयपुर ,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांगेस पार्टी ने इस देश में विकास तो नहीं कराया लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद को जरूर फैलाया हैं। श्री योगी बुधवार को यहां राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और भारतीय जनता पाटी के लोग आतंकवादियों को गोली मारते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक सत्रह चुनाव हार चुकी हैं इसलिए उन्हें अब सन्यास लेकर नानी के घर इटली जाना चाहिए और उनकी सेवा करें। इससे पूर्व श्री योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उदयपुर पहुंचने पर गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया।

युवक गैर लाइसेंसी बंदूक समेत गिरफ्तार

भरूच, ,(एजेंसी)। गुजरात के भरूच जिले में पुलिस ने अंकलेश्वर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले एक कश्मीरी युवक को बिना लाइसेंस की बंदूक और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पूंछ निवासी अहमद कुरैशी के पास से बंदूक के अलावा पांच जीवित कारतूस भी मिले हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि बिना लाइसेंस की बंदूक उसे कहा से मिली और वह कितने समय से गुजरात में रह रहा था।

पुणे में आग से 100 झुग्गियां जलकर हुई राख

पुणे ,(एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में आग लगने से 100 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दमकल विभाग ने यह जानकारी दी। दमकल प्रभारी प्रशांत रानपिसे ने बताया कि बुधवार को पुणे के शिवगंगानगर स्थित पाटिल इस्टेट लेन नंबर तीन स्थित झुग्गियों में अचानक आग लग गयी। आग बुझाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियों को भेजा गया। आग से 100 झुग्गियां जलकर राख हो गयीं। दमकल अधिकारी ने कहा, ''आग लगी झोपड़ियों में सात से आठ एलपीजी गैस सिलेंडर रखे होने के कारण आग और अधिक भड़क गई। झोपड़ियों में आग लगने के कारण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आग लगने के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं हैं। उन्होंने कहा झुग्गियों की संकरी गलियों के कारण दमकल कर्मियों को आग लगी हुई झुग्गियों तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

वनमानुष को वेश्यालय में बांधकर बनाया सेक्स वर्कर

बाली,(एजेंसी)। क्या कभी किसी वनमानुष को सेक्स वर्कर बनाने की बात सुनी है? आप इस सवाल से ही हैरान हो गए होंगे, लेकिन यह सच है। इंडोनेशिया के एक गांव में एक वनमानुष को सेक्स वर्कर बनाए जाने की खबर सामने आई है। पोनी नाम की मादा वनमानुष को फरवरी 2003 में बॉर्नियो जंगल से तब चुरा लिया गया था जब वह बहुत छोटी थी। उसे एक वेश्यालय में रखा गया था जहां ताड़ की खेती करने वाले किसान 2 पौंड देकर उसके साथ सेक्स किया करते थे। वनमानुष को वेश्यालय से बचाने वाले राहतकर्मियों का कहना है कि उसके पूरे शरीर को शेव कर दिया गया था। किसी ग्राहक के सामने पेश करने के दौरान उसे जूलरी पहनाई जाती थी और परफ्युम भी छिड़का जाता था।

पाकिस्तान ने पीओके की जनसांख्यिकी बदल दी है: सेना प्रमुख राउत

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है और उस तरफ के कश्मीरियों की पहचान योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दी गई है। उन्होंने कश्मीर में थोड़ी सी भी शांति होने पर सुरक्षा बलों को वापस बैरक में भेजने के सुझावों पर असहमति जताते हुए कहा कि इससे आतंकवादियों को अपने नेटवर्कों को फिर से जिंदा करने का वक्त मिल जाएगा और साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार दबाब बनाए रखने की जरूरत है।

यशवंतराव चव्हाण स्मरण व्याख्यान देते हुए रावत ने आतंकवादियों की शव यात्रा निकालने की अनुमति दिए जाने पर चिंता जताई और कहा कि यह आतंकवादियों को शहीदों के तौर पर पेश करता और संभवतः ज्यादा लोगों को आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का संदर्भ देते हुए रावत ने कहा, पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी से तथाकथित पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट-बाल्टीस्तान की जनसांख्यिकी बदल डाली है। इस बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता कि असल कश्मीरी कौन है। उन्होंने कहा कि क्या वह कश्मीरी है या पंजाबी है जो वहां आया और उस इलाके में कब्जा कर लिया।

गिलगिट-बाल्टीस्तान के लोग भी अब धीरे-धीरे वहां आकर बसने लगे हैं। अगर

कश्मीर में सुरक्षा बलों को वापस बैरक में भेजने से आतंकवादियों को नेटवर्कों को फिर से जिंदा करने का समय मिल जाएगा

हमारे तरफ के कश्मीरियों और दूसरे तरफ के कश्मीरियों के बीच कोई पहचान है तो यह पहचान वाली चीज धीरे-धीरे खत्म हो चुकी है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सफल अभियान का श्रेय स्थानीय लोगों को यह कहते हुए दिया कि वे मजबूत खुफिया जानकारियां देते हैं।

उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी और चीजें नियंत्रण में आ भी चुकी हैं लेकिन लगातार दबाव बनाए रखने की जरूरत है। रावत ने कहा कि स्थिति को उस स्तर तक लाना होगा जहां आतंकवादी समूह फिर से सिर न उठा पाएं। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम धीरे-धीरे ध्यान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि सेना सख्ती से काम नहीं लेना चाहती जिससे कि घाटी में हिंसा को बल मिले। प्रदर्शनों और बंदूक उठाने की संस्कृति से युवाओं को दूर रखने के लिए उनके साथ सकारात्मक तरीके से बात करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेना कश्मीर से मौलवियों को सद्भावना यात्राओं पर अजमेर शरीफ, आगरा तक लेकर जाएगी और उन्हें दिखाएगी कि भारत में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन नहीं हो रहा है।

मकर संक्रांति पर गांव-गांव में शाखा लगा चुनावी खिचड़ी बांटेगा आरएसएस

आरएसएस की शाखा में सियासी खिचड़ी की तैयारी

मेरठ ■ एजेंसी

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समेत दूसरे संगठनों द्वारा की जा रही तैयारी को आने वाले वक्त में और धार देने की योजना है। आरएसएस इस बार मकर संक्रांति पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम के साथ ही गांव-गांव में शाखा लगाकर लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सियासी सरगर्मी के बीच संघ की पूरी कोशिश चुनावी खिचड़ी बांटकर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की होगी।

दरअसल, आरएसएस जगह-जगह मकर संक्रांति सामाजिक समरसता कायक्रम के तौर पर उत्सव मनाता है। लेकिन इस बार तैयारियां कुछ अलग की जा रही हैं। आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक, इस बार मंडल के बजाए हर गांव में शाखा लगेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की टीमें

बनाई जा रही हैं, जिन्हें गांवों में मकर संक्रांति के दिन भेजा जाएगा। प्लान के तहत पंचायत स्तर पर संघ के मंडल विस्तारक माहौल तैयार करने लगे हैं। संघ की खास टीम अभी से इस काम की तैयारी में जुट गई है। संघ के परंपरागत कार्यक्रमों में मकर संक्रांति के दिन गणवेशधारी स्वयंसेवक कुछ खास जगह पर शाखाओं पर जुटते हैं। खिचड़ी पकाकर बांटी जाती है। सामाजिक समरसता के तौर पर इसे मनाया जाता है।

बढ़ता संघ शाखा का दायरा

संघ का मानना है कि मौजूदा वक्त में शाखा का दायरा देहात में बढ़ा है। इसलिए प्लान है शाखाओं को हर गांव तक ले जाया जाए। शाखा में हर आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी कराकर वहां मंदिर निर्माण और 2019 में हिंदूवादी सरकार के गठन के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद हो। संघ की दृष्टि से मेरठ प्रांत में 25 जिले हैं। मेरठ प्रांत में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के कुल 14 जिले हैं। मेरठ प्रांत में शाखाओं को बढ़ाने के लिए 55 सौ विस्तारक लगे हैं। संघ के 130 खंडों के 981 मंडलों के 10 हजार 580 से अधिक गांवों में और 191 नगरों में शाखाओं का संचालन हो रहा है। इन शाखाओं में लगातार स्वयंसेवकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए संघ इनमें और विस्तार चाहता है।

नई मुहिम को दिया महाअभियान का नाम: संघ के एक पदाधिकारी के मुताबिक, संघ ने मकर संक्राति की नई मुहिम को महाअभियान के तौर पर लिया है। संघ ने सभी न्याय पंचायत केंद्रों को मंडल मानकर एक-एक विस्तारक और उनके साथ एक सहयोगी को भेजा है।

बीजेपी के बिना बेहतर होगा देश: ममता

बलरामपुर ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के बिना देश बेहतर होगा। उन्होंने दावा किया कि देश में राजभवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक' सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों का भगवाकरण हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने 'बीजेपी भारत छोड़ो' का नारा देते हुए दावा किया बीजेपी के बिना देश बेहतर होगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं। इससे पहले ममता ने बीजेपी को रावण की उपासक बताया था।

पड़ोसी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर खोलेंगी मोर्चा

ममता में कहा, 'राजभवन से प्रधानमंत्री कार्यालय तक, सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों में बीजेपी ने अपना साइनबोर्ड टांग दिया है।' अगले लोकसभा चुनाव में तृणमूल के एक 'महत्वपूर्ण' भूमिका निभाने पर जोर देते हुए ममता ने कहा कि कई विपक्षी पार्टियों ने जनवरी में हमारी पार्टी के अनुसूचित रैली में शामिल होने पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'चंद्रबाबू नायडू, हार्दिक पटेल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनवरी में आयोजित होने वाली रैली में अपनी सहभागिता की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर अपने तरफ से एक नया मोर्चा खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने बीजेपी शासित असम और झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने बीजेपी को भगवान राम के बजाए रावण की उपासक बताया था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी भगवान के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास नहीं करती है।

बोर्ड विज्ञापित पदों में कमी नहीं करेगा: हाईकोर्ट

प्रयागराज ,(एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इंटर कालेजों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों को घटाने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं है। न्यायालय ने बोर्ड को नियमानुसार विज्ञापित पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत अधिक अभ्यर्थियों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ पैनल बनाने से इसमें शामिल सभी लोगों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। नियुक्तियां उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही होंगी लेकिन बोर्ड विज्ञापित पदों में कमी नहीं करेगा। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने संजय कुमार और 15 अन्य की याचिका पर बुधवार को यहां सुनवाई की। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के

ओझा ने पक्ष रखा। चयन बोर्ड ने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 909 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में इन पदों की संख्या घटाकर 720 कर दी गई। याची अधिवक्ता का कहना था कि बोर्ड को विज्ञापित पदों में कमी करने का अधिकार नहीं है, बल्कि नियम 12 (8) के तहत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अधिक अभ्यर्थियों का पैनल गठित होना चाहिए। इस पैनल में चयनित अभ्यर्थियों में सबसे अधिक मेरिट वाले को नियुक्ति दी जाएगी। चयन बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि, वास्तव में विज्ञापित पदों से भी कम सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हैं। कुल पदों में से बहुत से पद नियमितीकरण आदि में समायोजित हो जाते हैं। बड़ा पैनल बनाने से चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाती, जिससे उनको मायूस होना पड़ता है। इससे बचने के लिए पदों की संख्या में कमी की गई है। इस दलील पर असहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय का कहना था कि बोर्ड नियम 12(8) के तहत चयन प्रक्रिया अपनाने को बाध्य है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर बोर्ड संशोधित पैनल का चयन करे।

ब्लाइंड मर्डर मामले में एक युवक गिरफ्तार

गुरुग्राम ,(एजेंसी)। हरियाणा के गुरुग्राम में चार नवंबर को हुए एक ब्लाइंड मर्डर मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का बुधवार को दावा किया। ज्योति पार्क निवासी महेंद्र वर्मा उर्फ बिंदु की लाश गांव धनकोट के पास मिला था। हत्या गोली मारकर की गई थी तथा शव उनकी स्कार्पियो गाड़ी के पास ही मिला था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी गायब जो कि मृतक अपने साथ रखता था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्मा को दी केस डायरी देखने की इजाजत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक ए के शर्मा को एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की फाइल का सीवीसी कार्यालय में निरीक्षण करने की बुधवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने अपने आदेश की अवधि सात दिसंबर तक बढ़ा दी। अस्थाना ने रिश्वत मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। अदालत ने सीवीसी कार्यालय में मामले की फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी जहां निरीक्षण के समय सीबीआई के पुलिस अधीक्षक सतीश डागर मौजूद रहेंगे। वर्मा के खिलाफ जांच के लिए सतर्कता निकाय को निर्देश दिये जाने संबंधी सुको के आदेश के बाद मामले से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को जांच पड़ताल के लिए सीवीसी के पास भेजा गया था। शर्मा को भी फाइलों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को सीवीसी कार्यालय में जाने के लिए कहा गया है। शर्मा की ओर से पेश वकील नियाजी ने कहा कि दस्तावेज निजी नहीं हैं और वे सीबीआई से भी जुड़े हैं, लेकिन वह सिर्फ संवेदनशील सामग्री को इंगित करना चाहते हैं जिसे कोर्ट और एजेंसी द्वारा देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि शर्मा द्वारा दिए स्तावेजों को अगले आदेशों तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाये। अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों अमरेन्द्र शरण और दयान कृष्णन ने कहा कि शर्मा को सीबीआई को सामग्री देनी चाहिए और अदालत में उनके द्वारा दिए दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है तो उन्हें भी इनके निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।

देहरादून में पर्यटकों के लिए खुला मोतीचूर रेंज का प्रवेश द्वार

देहरादून,(एजेंसी)। उत्तराखंड में प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज का प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए बुधवार सुबह खोल दिया गया। मोतीचूर रेंज का प्रवेश द्वार हर वर्ष 15 नवंबर तक खोल दिया जाता है लेकिन इस बार किसी कारणवश इसे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि वन मंत्री हरख सिंह रावत के दखल के बाद तय अवधि से पहले प्रवेश द्वार खोलने पर सहमति बनी है।

मोतीचूर रेंज अधिकारी प्रमोद ध्यानी ने बताया कि बुधवार की सुबह विधिवत रूप से रेंज का प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वन्यजीव प्रेमी पर्यटकों के लिए बनाए गए 12 किमी नए ट्रैक को दुरुस्त करा दिया गया था जिस पर पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पार्क में पर्यटकों को प्रवेश द्वार से अधिकृत खुली जीप में प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। रेंज में हिरण, गुलदार, हाथी और टाइगर आदि कई अन्य प्रजाति के वन्यजीवों को देखने का पर्यटकों को मौका मिलेगा।

केंद्र की बड़ी जीत, आखिर चीन ने मान ही लिया पीओके को भारत का हिस्सा!

नई दिल्ली,(एजेंसी)। चीन ने आखिरकार मान ही लिया कि पीओके पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि 23 नवंबर को चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीजीटीएन ने कराची में चीनी दूतावास पर हुए हमले की खबर दिखाई थी। इसी दौरान पाकिस्तान का नक्शा दिखाते हुए चीन के चैनल ने पीओके को भारत में दिखाया था।

पाकिस्तान में चीनी दूतावास पर हुआ हमला गलत

सीजीटीएन चीन का सरकारी चैनल है और इस चैनल पर वहीं खबरें चलती हैं जिस पर चीन के सरकार की मंजूरी होती है। चीन मामलों के जानकारों का कहना है कि इसे साफतौर पर चीन की पाकिस्तान को चेतावनी माना जा सकता है। विशेषज्ञों की मानें, तो चीन इस तरह से पाकिस्तान को चेताना चाहता है कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास पर हुआ हमला गलत है। साथ ही आगे से चीन के दूतावास पर किसी तरह का आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हम इसे भारत और चीन के मजबूत होते संबंधों के तौर पर भी देख सकते हैं। इसे भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। भारत के लिए यह खुश होने का मौका है। चीन ने अगर पीओके को भारत की सीमा में दिखाया है, तो कुछ सोच समझकर ही ऐसा किया होगा। हालांकि, इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, यह अभी साफ नहीं है।

सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ने बनाई पार्टी

सीबीआई इन दिनों आंतरिक कलह से जूझ रही है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच मचा घमासान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सीबीआई मे पूर्व संयुक्त निदेशक रहे वीवी लक्ष्मीनारायण ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि अगले साल वह चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सीबीआई में अफसरों के बीच आंतरिक लड़ाई का मामला पिछले तीन महीने से चल रहा। एक दूसरे के खिलाफ घूसखोरी के आरोपों पर मचे घमासान के बीच बीते दिनों नियुक्ति कमेटी ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया।

चुनावी रैली में बजरंग बली को दलित कहने का आरोप

योगी को नोटिस भेजकर मांफी मांगने को कहा

जयपुर,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित रूप से एक चुनावी रैली के दौरान हिंदुओं के आराध्य हनुमान को दलित और वंचित बताया जाना राजस्थान के कई लोगों को रास नहीं आया है। सर्व ब्राह्मण समाज ने तो इस मामले में योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। सर्व ब्राह्मण समाज का कहना है कि बजरंग बली न तो दलित हैं, न वंचित और न ही लोकदेवता। वकील के जरिए भेजे नोटिस में योगी आदित्यनाथ से इस मामले में माफी मांगने को कहा है और तीन दिन में ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।

बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में राज्य में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलवर के मालाखेड़ा में कहा था कि बजरंग बली ऐसे लोकदेवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं दलित हैं वंचित हैं। इससे नाराज ब्राह्मण समाज ने नोटिस में कहा है कि हनुमान भगवान हैं। उन्हें वंचित और लोकदेवता बताना न केवल उनका बल्कि लाखों हनुमान भक्तों का अपमान है।

प्रतिबंध अखाड़े से भी निलंबित, मान-सम्मान नहीं मिलेगा और कुंभ में अखाड़े में प्रवेश भी वर्जित रहेगा

दाती महाराज से महामंडलेश्वर की पदवी छिनी

प्रयागराज

शिष्या का यौन शोषण करने के आरोपों में घिरे दाती महाराज को श्रीपंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने निलंबित कर दिया है। अखाड़े ने उनकी महामंडलेश्वर की पदवी और अखाड़े की सदस्यता को समाप्त करते हुए कुंभ में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है।

श्रीपंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत राम सेवक गिरी के मुताबिक, दाती महाराज को अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में अब कोई मान-सम्मान नहीं मिलेगा और कुंभ में अखाड़े में उनका प्रवेश भी वर्जित रहेगा। हालांकि, सामान्य श्रद्धालु के रूप में उनके कुंभ में आने पर कोई रोक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यौन शोषण मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट से दोष मुक्त करार नहीं दे दिए जाते, तब तक अखाड़े में उनकी वापसी भी संभव नहीं है।

दाती महाराज पर शिष्या से रेप का आरोप, कोर्ट में चल रहा है मामला

महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत राम सेवक गिरी ने कहा, अखाड़ा किसी दागी संत को अपने साथ नहीं रख सकता है। कोर्ट से निर्दोष साबित होने तक उन्हें निलंबित रखा जाएगा और यदि कोर्ट उन्हें दोषी ठहराता है तो ही सजा भुगतेंगे। गौरतलब है किदाती महाराज विवादित रहे हैं। दाती महाराज के दिल्ली में पाली स्थित आश्रम की एक शिष्या ने उन पर दुष्कर्म का गम्भीर आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि दाती महाराज और उनके शिष्यों ने 25, 26 और 27 मार्च 2016 को उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता ने दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को स्थानान्तरित करने की पीड़िता की याचिका को भी स्वीकार कर लिया है।

दखल

आदिवासियों की निजता में दखल क्यों

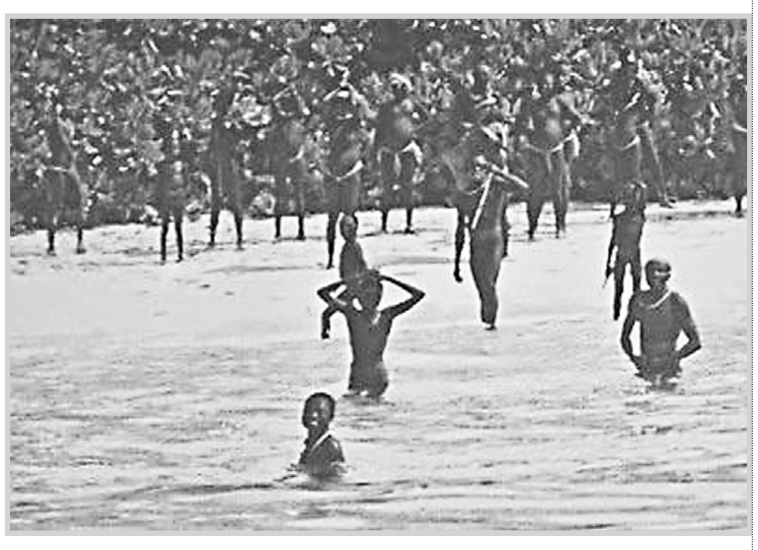

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल द्वीप पर एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाऊ की सेंटिनल आदिवासी समूह के लोगों द्वारा की गई हत्या ने कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल यह कि जब ये आदिवासी हमारी दुनिया में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते तो हम क्यों वहां जाकर उनकी निजता को चोट पहुंचा रहे हैं। खासकर दूर देश से आने वाले पर्यटकों को इस बात को जानना होगा।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल द्वीप पर एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाऊ की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पोर्ट ब्लेयर से प्रकाशित अखबार के अनुसार इस वरदात के पीछे सेंटिनल आदिवासी समूह का हाथ है। इसे उनके इलाके में पहुंचने पर धनुष-बाण से मारा गया। हालांकि अपनी मौत को लेकर एलन पूर्व से ही सशंकित था, क्योंकि उसने अपने परिजनों को लिखे-पत्र में बताया था कि 'वह इस यात्रा में मारा भी जा सकता है। अलबत्ता वह इन आदिवासियों के हाथों मारा भी जाए तो इन पर नाराजगी जताने की जरूरत नहीं है।' दरअसल एलन पर इसाई धर्म का अफीम की तरह नशा सवार था और वह इन आदिवासियों को वाइबिल का पाठ पढ़ाना चाहता था। यह जानकारी अमेरिकी अखबार वशिंगटन पोस्ट ने दी है। पुलिस ने इस मामले में एलन को द्वीप पर ले जाने वाले मछुआरों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एलन ने इन्हें 25,000 रुपए बतौर किराया दिया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक विलुप्ति के कगार पर खड़े सेंटेनलीज समुदाय के आदिवासियों की संख्या महज 40 है। हालांकि, अखबार में यह संख्या 15 बताई गई है, जिनमें 12 पुरुष और तीन महिलाएं 10 झोपड़ियों में रहते हैं। इस द्वीप के रहवासियों से किसी भी प्रकार का संपर्क साधना अवैध है तथा द्वीप के लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

वैसे तो इस द्वीप पर जाना गैरकानूनी है, लेकिन इसी साल अगस्त में केंद्र सरकार ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप तथा अन्य 28 द्वीपों पर विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा कमाने के नजरिए से ही दी गई है। जबकि ये वनवासी समूह किसी भी पराए व्यक्ति का अपनी निजता में दखल बर्दाश्त तक नहीं करते हैं। ये लोग पिछले 60 हजार साल से यहीं रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह समुदाय अफ्रीका के पहले मानवों के वंशज हैं। इनका व्यवहार बेहद उग्र और क्रूर है। इसलिए अमेरिकी नागरिक का यहां जाने की कोशिश करना उचित नहीं था। लगभग इसी तर्ज पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने इसी द्वीप समूह में रहने वाले जारवा आदिवासियों से अनाधिकृत रूप से संपर्क साधकर फिल्म बनाई थी। जिसमें इनकी नग्नता को प्रमुख रूप से दिखाया गया था। हालांकि इस द्वीप के पांच नोटिकल मील के व्यास में जाना मछली पकड़ना और सेंटिनल आदिवासियों के फोटो खींचना व वीडियो बनाना अपराध के दायरे में हैं, इस कानून को तोड़ने पर तीन साल की सजा का प्रावधान हैं। जब किसी भी समाज की दशा और दिशा अर्थतंत्र तय करने लगते हैं तो मापदंड तय करने के तरीके बदलने लग जाते हैं। यही कारण है कि हम जिन्हें सभ्य और आधुनिक समाज का हिस्सा मानते हैं, वे लोग प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों को इंसान मानने की बजाय जंगली जानवर ही मानते हैं।

आधुनिक कहे जाने वाले समाज की यह ऐसी विडंबना है, जो सभ्यता के दायरे में नहीं आती है। आधुनिक विकास और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वन कानूनों में लगातार हो रहे बदलावों के चलते अंडमान में ही नहीं देश भर की जनजातियों की संख्या लगातार घट रही है। आहार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी होती जा रही है। इन्हीं वजहों के चलते अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग दुर्गम टापुओं पर जंगलों में समूह बनाकर रहने वाली जनजातियों का अन्य समुदायों और प्रशासन से बहुत सीमित संपर्क है। यही वजह है कि जारवा आदिवासियों की संख्या घटकर 381 रह गई है। एक अन्य टापू पर रहने वाले ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोगों की आबादी केवल 97 के करीब है। इन लोगों में प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी कम होती है कि ये एक बार बीमार हुए तो इनका बचना मुश्किल होता है। एक तय परिवेश में रहने के कारण इन आदिवासियों की त्वचा बेहद संवेदनशील हो गई है। लिहाजा यदि ये बाहरी लोगों के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो ये रोगी हो जाते हैं और उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। एक दशक पहले तक ये लोग पूरी तरह निर्वस्त्र रहते थे, लेकिन सरकारी कोशिशों और इनकी बोली के जानकार दुभाषियों के माध्यम से समझाइश देने पर ये लोग थोड़े-बहुत कपड़े पहनने अथवा पत्ते लपेटने लगे हैं, लेकिन अब भी कई निर्वस्त्र ही रहते हैं।

भारत की सांस्कृतिक विविधता एक अनूठी खूबसूरती है। यहां विभिन्न आदिवासी समुदायों को अपने पुरातन एवं सनातन परिवेश में रहने की स्वतंत्रता हासिल है, जबकि मानवाधिकारों की वकालत करने वाले अमेरिका में आदिम जनजातियों को सुनियोजित ढंग से समाप्त किया जा रहा है। अमेरिकी देशों में कोलंबस के मूल्यांकन को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण सामने आए हैं। एक दृष्टिकोण उन लोगों का है, जो अमेरिकी मूल के हैं और जिनका विस्तार व वर्चस्व उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के अनेक देशों में है। दूसरा दृष्टिकोण या कोलंबस के प्रति धारणा उन लोगों की है, जो यह दावा करते हैं कि अमेरिका का अस्तित्व ही हम लोगों ने खड़ा किया। इनका दावा है कि कोलंबस इन लोगों के लिए मौत का कहर लेकर आया क्योंकि कोलंबस के आने तक अमेरिका में इन आदिम समूहों की आबादी 20 करोड़ के करीब थी, जो अब घटकर 10 करोड़ के करीब रह गई है। इतने बड़े नरसंहार के बावजूद अमेरिका में अश्वेतों का जनसंहार लगातार जारी है। ब्रिटेन के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहां नस्लीय आधार पर भारत-मूल के लोगों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं। शोषण व सुनियोजित संहार के ऐसे ही पैरोकारों का एक दल हमारे यहां भी पैदा हो गया है। जिसमें योजनाकर और अर्थशास्त्री शामिल हैं। ये भूमि, जंगल और खनिजों को आर्थिक संपत्ति मानते हैं। इनका कहना है कि इस प्राकृतिक संपदा पर दुर्भाग्य से ऐसी छोटी व मझोली जोत के किसानों और वनवासियों का वर्चस्व है, जो अयोग्य और अक्षम हैं। सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि के लिए जरूरी है, ऐसे लोगों से खेती योग्य भूमियां छीनी जाएं और उन्हें विशेष व्यावसायिक हितों, शॉपिंग मालों, शहरीकरण और पर्यटन के लिए अधिग्रहण कर विकसित किया जाए। इसी तर्ज पर जिन जंगलों और खनिज ठिकानों पर जन-जातियां आदिकाल से रहती चली आ रही हैं, उन्हें विस्थापित कर संपदा के ये अनमोल क्षेत्र औद्योगिक घरानों को उत्खनन के लिए सौंप दिए जाएं।

इस मकसद पूर्ति के लिए 'क्षतिपूर्ति वन्यरोपण विधेयक 2008' बिना किसी बहस-मुवाहिशे के पारित करा दिया गया था। जबकि इसके मसौदे को जनजातियों, वनों और खनिज संरक्षण की दृष्टि से गैर-जरूरी मानते हुए संसद की स्थायी समिति ने खारिज कर दिया था। लेकिन कंपनियों को सौगात देने की कड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समिति की सिफारिश को दरकिनार कर यह विधेयक पारित करा दिया। इसी तर्ज पर सभी संघ शासित क्षेत्रों में इस सेंटिनल द्वीप सहित 28 अन्य द्वीपों को 31 दिसंबर 2022 तक प्रतिबंधित क्षेत्र की सूची से बाहर कर दिया है। इसे हटाने का आशय यह हुआ कि विदेशी लोग सरकार की अनुमति के बिना इन द्वीपों पर आ जा सकेंगे। विदेशी पर्यटकों का यही हस्तक्षेप इनकी संख्या घटने का कारण बन रहा है। इन जनजातियों की निजता में यह हस्तक्षेप शर्मनाक पहलू होने के साथ अमानवीयता का बर्ताव है। दरअसल ये वनवासी नहीं जानते कि कथित रूप से सभ्य मानी जाने वाले दुनिया में नग्नता बिकती है और हम उनकी सभ्यता को समझे बिना वहां पहुंच जाते हैं।

■ **प्रमोद भार्गव**
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

पाक को फिर जोर का झटका

भारत ने पाकिस्तान की तरफ से मिले सार्क सम्मेलन के न्योते को ठुकरा दिया है। भारत 2016 में भी पाक में होने वाले सम्मेलन का बहिष्कार कर चुका है। सही भी है आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ संभव नहीं है। पाक को अपनी करतूतों पर लगाम लगानी ही होगी।

पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में छवि सुधारने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में उसकी ओर से भारत को सार्क सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, मगर उसकी दिखावे की कोशिशों को फिर से झटका लगा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आया सार्क समिट का न्यौता ठुकरा दिया है। पाक से लगातार बढ़ते हुए तनावों को देखते हुए अब आपसी बातचीत की गुंजाइश नहीं रह गई है और कोई भी वार्ता संभव नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) सम्मेलन का आयोजन इस साल पाकिस्तान में होना है। 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन साल 2016 में पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये सम्मेलन रद्द करना पड़ा था। सार्क में दक्षिण एशिया के आठ देश सदस्य हैं, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका हैं। आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था।

एक ओर करतारपुर कॉरिडोर खोल रहे पाकिस्तान ने दूसरी ओर से सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित करने का दांव चला जिसका भारत ने कोई तरजीह नहीं दी और कहा कि उसे आमंत्रित करने की जरुरत नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि इस साल प्रस्तावित सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा जाएगा, जिसके जवाब में भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी ने साफ कर दिया कि भारत सार्क का अभिन्न हिस्सा है और उसे विशेष निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वैसे, इस बार भी सम्मेलन होने की संभावना नहीं दिख रही क्योंकि कई सदस्य देशों में राजनीतिक हलचल की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में चुनाव होने हैं जबकि श्रीलंका में राजनीतिक संकट बना हुआ है। इस लिहाज से देखें तो भारत के गैरहाजिर होने के बाद लगातार तीसरे वर्ष सार्क सम्मेलन के रद्द होने की पूरी संभावना बन गई है।

अब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इमरान खान के नेतृत्व में नई सरकार सार्क सम्मेलन को लेकर उत्साहित दिख रही है और सरकार चाहती है कि सभी सदस्य देश सम्मेलन में शामिल हों। उसे डर है कि सितंबर, 2016 की तरह इस बार भी कहीं सदस्य देश इसमें शिरकत की योजना स्थगित न कर दें और सम्मेलन रद्द न करना पड़ जाए। पिछले दो साल से पाकिस्तान सार्क सम्मेलन का आयोजन नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उस पर इस बात का काफी दबाव है कि सम्मेलन को सफल तरीक से आयोजित किया जाए। लेकिन अब जब भारत ने अपनी तरफ से स्थिति साफ कर दी है, तो पाक अपना दामन साफ दिखाने के बजाय सीमा पार से आ रहे आतंकवाद पर लगाम लगाए और दोगलापन खत्म करे।

सौहार्द्रपूर्वक निकले मंदिर का हल

राम मंदिर को लेकर जब भी बात निकली है, तब-तब देश में माहौल कटुता का बना है। एक-दो मौकों पर हिंसा तक फैली है। इसलिए फिर से ऐसा न होने पाए, सभी को आगे आना ही होगा। राम मंदिर का हल अगर सौहार्द्रपूर्वक निकलता है, तो उसका संदेश देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाएगा। लिहाजा मुस्लिम मंच अपने स्तर पर जो पहल कर रहा है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए।

अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रुख ने माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। दोनों ही संगठनों ने राम मंदिर के लिए सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव बनाने का पुरजोर प्रयास किया है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हिंदू संगठनों की कोशिश के बीच पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल से एक मंच ने देश में सद्भावना फैलाने की शानदार और सकारात्मक हुंकार भरी है। कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे' के नारे के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राम मंदिर बनाने पर सहमति जताते हुए एक अभियान शुरू किया है। इस पूरे प्रयास में मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलावा मुस्लिम जनता को भी मनाने व समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह कार्यक्रम 17 नवंबर से शुरू हुआ है और 30 नवंबर तक पूरे देश में जारी रहेगा।

यह संगठन हर जिला स्तर पर कार्यक्रम द्वारा राम मंदिर बनाने के समर्थन का प्रचार व प्रसार करेगा। इसमें सबसे आकर्षण भरी बात यह होगी कि कुरान और हदीस से अहम बातों को लेकर व मोहम्मद रसूल के असूलों के समावेश के साथ अपने विचारों को दोनों धर्मों के लोगों को मिलाने का प्रयास होगा। जैसा कि हूजूर साहब (पैगम्बर हजरत मोहम्मद) ने अपने जीवन काल में कई चीजों में बदलाव करके बेहद सरल बनाने के साथ अन्य धर्मों के साथ मेल-मिलाप के लिए बहुत बातें कही थीं। यहां अरबी भाषा की एक कहावत के साथ उनके पैगाम को समझना पड़ेगा। 'लकूम दिनकुम वालिया दीन' जिसका अर्थ है 'तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक।' अर्थात् कोई भी धर्म किसी पर कुछ भी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती न करे। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि धार्मिक बातों की चपेट में अब अशिक्षित वर्ग ही नहीं पढ़ा लिखा तबका भी शिकार होने लगा है। आज तक यह देश आपसी भाईचारे के आधार पर चला आया है व वर्तमान और भविष्य में भी ऐसे ही चलेगा।

लेकिन अब बात यह आ जाती है कि उनकी इन बातों पर कितने लोग अमल करते हैं। फिजाओं में जहर घोलने का काम तो सब करते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या मिठास व प्यार फैलाने वाले आज की दुनिया को बदलने में सक्षम हो पाएंगे। देश में ऐसे कितने लोग हैं जो इस सद्भावना भरे संदेश पर अमल करेंगे? देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जैसा देश बिना आपसी तालमेल के नहीं चल सकता क्योंकि यह एक धर्म निरपेक्ष देश है। हमारे यहां हर क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा और अन्य तमाम धार्मिक स्थल होते हैं। यहां तो अजान भी सुनाई देती है तो आरतियां व गुरबानियां भी। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। देश को भ्रमित करने वाली बातों के सिवाय अपनी तरक्की की ओर अग्रसर होते हुए हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। देश में लाखों मस्जिद व मंदिर हैं लेकिन लोग अब किधर जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि देश सरकारें नहीं, बल्कि वाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं। सोशल मीडिया का लोग फायदा कम लेते हैं भ्रमकता भरे मैसेज से अपना व देश का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। यहां बहुत एहतियात बरतनी होगी क्योंकि किसी भी रिश्ते को समझने और बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन टूटने या खराब होने में बस पल भर का ही खेल होता है।

एक पुरानी मिसाल है कि रिश्तेदार आपके बाद में काम आएगा पहले पड़ोसी ही आएगा। अब आपका वह पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान या अन्य किसी धर्म का भी हो सकता है। रिश्तों और प्यार को बनाए रखने के लिए धर्म की नहीं इंसानियत की गंभीरता समझनी जरूरी होती है। अतः देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखिए व हर निर्णय का दिल खोलकर स्वागत रखने के लिए तैयार रहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनावाई चल रही है और इसको लेकर देश के कई छोटे बड़े संगठनों के अलावा बड़ी पार्टियां भी अब खुलकर सामने आ गई हैं। जैसा कि वहां लगातार शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। मुद्दा धार्मिक और मार्मिक हो सकता है लेकिन सवा सौ करोड़ भारतीयों को इस पर निर्णय आने का इस तरह इंतजार है जैसे यह हिंदुस्तानियों का आपस में ही विश्व कप हो रहा हो जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अंधकार में झोंक रहे हैं। मौजूदा समय में अयोध्या में 24 मस्जिदें और तीन मजार अभी भी हैं। इसके सिवाय तमाम मंदिर भी हैं इसलिए दोनों धर्मों के लोगों को ऐसी स्थिति में एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए कि धार्मिक स्थलों के चक्कर में न पड़ें।

बहरहाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कई हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल होंगे। इसमें मंदिर निर्माण को लेकर सब के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। यह एक अच्छा प्रयास इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि इसमें तमाम उन सभी पार्टियों की हकीकत सामने आ जाएगी तो बाहरी मन से कहते हैं कि राम मंदिर बनाओ और उनके मन में इसके विपरीत ही कुछ चल रहा होता है। इसका सबसे सजीव उदाहरण पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल हैं, जो राम मंदिर की खिलाफत में केस लड़ रहे हैं। नौ दिसंबर को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर को लेकर एक धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस ऐतिहासिक कदम से यह तो तय हो जाता है कि देश में कुछ घटिया राजनीति करके धर्मों के आधार पर देश का वर्गीकरण कर रहे हैं वहीं मुस्लिम संगठनों ने एक आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। विपक्ष लगातार अपने बयानों से मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने स्वयं ही इस तरह की पहल करते हुए दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं को साथ मिलाकर नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है। विश्व हिंदू परिषद भी हर अथक प्रयास करके राम मंदिर मामले में कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी केंद्र पर सौंप दी। लेकिन देश की तमाम पार्टियों, संगठनों और जनता के मन में प्रश्न यह आ रहा है कि इस मामले में कोर्ट किस पहलू का इंतजार कर रहा है।

कई संगठन और पार्टी राम मंदिर मुद्दे के लिए कार्यरत हैं लेकिन हमें देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखना होगा क्योंकि वह जो भी निर्णय लेगी सोच समझकर लेगी। इसलिए हम इस मुद्दे पर आपसी रिश्तों को कतई खराब न होने दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। किसी भी देश की तरक्की का भार युवाओं वर्ग पर टिका होता है और देश में युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अब मुस्लिम मंच ने जो पहल की है, उसे इसी दायरे में रखकर देखने की जरूरत है। सही मायने में कहा जाए तो किसी भी समस्या का सामना व समाधान आपसी सौहार्द्र से ही संभव है। वह भी तब जब मामला धार्मिक हो। लिहाजा मुस्लिम मंच ने जो पहल की है, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और जो संभव हो, मदद करनी चाहिए। राम मंदिर को लेकर जब भी बात निकली है, तब-तब देश में माहौल कटुता का बना है। एक-दो मौकों पर हिंसा तक फैली है। इसलिए फिर से ऐसा न होने पाए, सभी को आगे आना ही होगा। राम मंदिर का हल अगर सौहार्द्रपूर्वक निकलता है, तो उसका संदेश सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाएगा।

■ **योगेश कुमार सोनी**
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन के लिए भारत को न्योता भेजा गया था, मगर उसने ठुकरा दिया। मगर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और सम्मेलन भी कराएंगे।

मो. फैसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, पाक

आतंकवाद व दोस्ती में जब तक पाक फर्क करना नहीं शुरू करेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। भारत कई मंचों पर पाक के साथ दोस्ती की राह आसान करने की नाकाम कोशिश की है।

रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

सत्यार्थ

जब तैमूर का अहंकार टूटा

दुनिया के कट्टर और खूंखार बादशाहों में तैमूरलंग का नाम भी आता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहंकार और जवाहरात की तृष्णा से पीड़ित तैमूर ने एक बार तो विशाल भू-भाग को रौंदकर रख दिया था। उसकी क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि बगदाद में उसने एक लाख मरे हुए लोगों की खोपड़ियों का पहाड़ खड़ा कराया था। एक बार बहुत से गुलाम पकड़कर तैमूरलंग के सामने लाए गए। तुर्किस्तान का विख्यात कवि अहमदी भी दुर्भाग्य से उन गुलामों के साथ पकड़ा गया। जब अहमदी तैमूर के सामने उपस्थित हुआ, तो खतरनाक हंसी हंसते हुए उसने दो गुलामों की ओर इशारा करते हुए अहमदी से पूछा- सुना है कि कवि बड़े पारखी होते हैं। क्या तुम बता सकते हो, इन गुलामों की कीमत क्या होगी। अहमदी ने उत्तर दिया- इनमें से कोई भी पांच हजार अशर्फियों से कम कीमत का नहीं। अच्छा, तो बताओ मेरी कीमत क्या होगी, तैमूर ने बड़े अभिमान से पूछा। यही कोई 25 अशर्फी, निश्चिंत भाव से अहमदी ने उत्तर दिया। इतना सुनते ही तैमूर क्रोध से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला- बदमाश! इतने में तो मेरी सदरी भी नहीं बन सकती, तू यह कैसे कह सकता है कि मेरा मूल्य 25 अशर्फी है। अहमदी ने बिना किसी डर के उत्तर दिया- जी! बस, यह कीमत भी उसी सदरी की ही है, आपकी तो कुछ नहीं, क्योंकि जो मनुष्य पीड़ितों की सेवा नहीं कर सकता, बड़ा होकर छोटों की रक्षा नहीं कर सकता, असहायों और अनाथों की जो सहायता नहीं कर सकता है, उस इंसान का मूल्य तो चार कौड़ी भी नहीं। उससे अच्छे तो ये गुलाम ही बेहतर हैं, जो किसी के काम तो आते हैं। अहमदी की यह बात सुनते ही तैमूर का अहंकार चूर-चूर हो गया।

■ **राधा नाचीज**

सार समाचार

नहीं छट रहे कैलिफोर्निया से संकट के बादल, जंगलों में आग के बाद भारी बारिश के आसार

सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहे तूफान के कारण गुरुवार को यहां बारिश हुई। इससे अग्निकांड का शिकार जंगलों वाले क्षेत्रों में अवशेषों के बहने का खतरा उत्पन्न हो गया है जो सियेरा नेवादा जाने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्यूटे काउंटी की प्रवक्ता कैली लुट्ज ने कहा कि एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम पेराडाइज के इलाके में बाढ़ और कीचड़ संभावित इलाकों की पहचान करने में जुटी है। इसके अलावा जल निकासी की सफाई और गिर सकने वाले पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय मौसम विभाग सेवा की प्रवक्ता सिंडी मैथ्यूज ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के उत्तरपूर्व में 140 मील (225 किलोमीटर) के जले हुए हिस्से में गुरुवार को एक इंच तक बारिश हो सकती है। करीब 27 हजार की आबादी वाले इस कस्बे को आग लगने की घटना के बाद तीन हफ्ते पहले खाली कराने का आदेश जारी किया गया था। उस आग में हजारों घर तबाह हो गए थे जबकि 88 लोगों की मौत हो गई थी। शैरिफ कोर्य होनेआ ने कहा कि यदि तूफान ने सड़कों को ठीक करने और बिजली आपूर्ति बहाली के प्रयासों को क्षति नहीं पहुंचायी तो लोग अगले हफ्ते से पहले अपने घरों में लौट सकते हैं।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की लोकप्रियता में 50 प्रतिशत तक गिरावट : सर्वेक्षण

सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई-इन की लोकप्रियता में पहली बार 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। बृहस्पतिवार को जारी एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। इस सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि देश में आर्थिक संकट गहरा हुआ है और उत्तर कोरिया के साथ सुलह की दिशा में तेज होते प्रयासों को लेकर चिंता भी है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के मद्देनजर मई में मून की लोकप्रियता 80 प्रतिशत के करीब थी। यह किसी भी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के लिए अपने कार्यकाल के पहले साल के आखिर में अब तक का सर्वाधिक स्कोर था। बहरहाल, इस सप्ताह रीयलमीटर द्वारा 1,508 लोगों पर कराये गये सर्वेक्षण में मून की लोकप्रियता का स्तर 48.8 प्रतिशत तक गिर गया। उनकी लोकप्रियता में गिरावट का सिलसिला नौवें सप्ताह में भी जारी रहा। सर्वेक्षक के मुताबिक, लोकप्रियता में यह तेज गिरावट देश में विकास की गति रुकने, बढ़ती बेरोजगारी और आय में जारी असमानता के बीच आर्थिक संकट को लेकर लोगों में व्याप्त असंतोष दर्शाती है।

भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान जताएगा हक, इमरान कैबिनेट 5वां प्रांत बनाने पर लेगी फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर के शुरू होने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पंजाब का रास्ता खुलने के बाद पाकिस्तान ने विवादित गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र मामले पर आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है. पाकिस्तान औपराचिक तौर पर गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत घोषित करने की तैयारी कर रहा है.

लीगल स्टेट की समीक्षा के लिए कमेटी गठित

पाकिस्तान सरकार की ओर से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के लीगल स्टेटस की समीक्षा के लिए एक कमिटी गठित की गई है. माना जा रहा है कि लीगल स्टेटस की समीक्षा होने के बाद पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत घोषित कर सकता है.

जम्मू कश्मीर का हिस्सा है गिलगित-बाल्टिस्तान

आपको बता दें कि भारत इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताता है. नॉदर्न एरियाज के नाम से चर्चित जम्मू-कश्मीर के इसी टुकड़े को अब पाकिस्तान ने अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की योजना बनाई है. हालांकि भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है. दरअसल, पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अगुवाई वाली सात जजों की बेंच ने अक्टूबर में सरकार को निर्देश दिया था कि वह पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के बराबर लाने के लिए इस क्षेत्र के लीगल स्टेटस की समीक्षा करें.

इमरान सरकार ने बनाई 10 सदस्यों की कमिटी

अब पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने उसी फैसले पर अमल करते हुए 10 सदस्यों की एक कमिटी बना दी है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष पैनल की सुझाव को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया था. यह पैनल क्षेत्र के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित किया गया था.

जज ने आर्टिकल 370 का भी किया था जिक्र

बेंच के एक सदस्य ने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया था कि अगर भारत अपने संविधान के आर्टिकल 370 में संशोधन कर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दे सकता है तो पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा क्यों नहीं दे सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं और उन्हें सभी अधिकार मिलने चाहिए.

प्रांत का दर्जा कैसे दें, सुझाएंगे तरीके

अब सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के तरीके सुझाएगी. गौरतलब है कि यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत विवादित है. भले ही इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो लेकिन भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है. सुप्रीम कोर्ट ने 32 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए थे. याचिकाओं में विवादित क्षेत्र के संवैधानिक दर्जे को लेकर चिंता जताई गई थी. इनमें मुख्य याचिका गिलगित-बाल्टिस्तान बार काउंसिल की ओर से उसके वाइस-चेयरमैन जावेद अहमद की ओर से फाइल की गई थी.

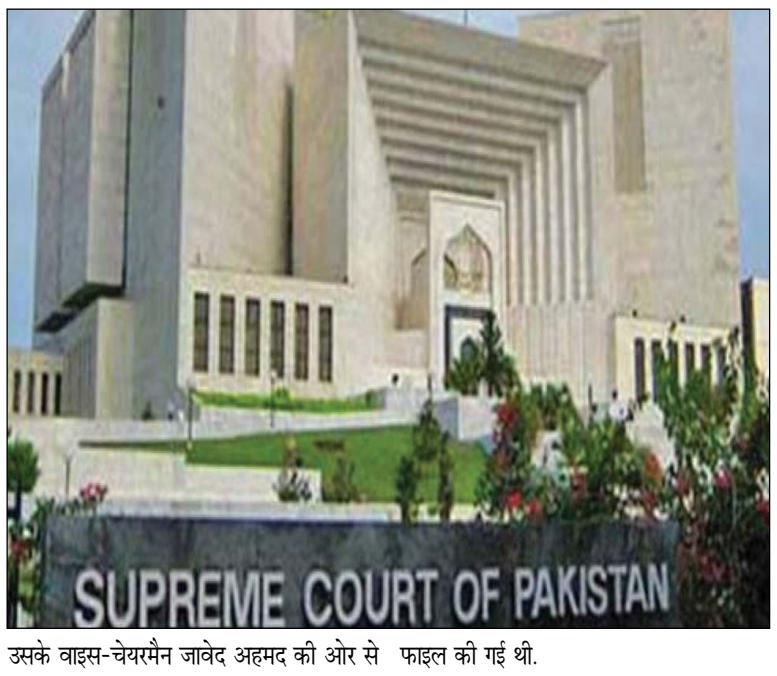

इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, पीएम मोदी से कहा- चलिये बात करते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ अमन चाहते हैं। यहां के लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान की संभावना पर कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की जमीन का बाहर आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत देना हमारे हित में नहीं है। इमरान खान ने मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने पर कहा कि हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। जमात-उद-दावा प्रमुख पर पहले से ही शिकंजा कसा हुआ है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा ने कहा कि शांति के प्रयास एक तरफा नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा, हम नयी दिल्ली के संकेत के लिए भारत में होने वाले चुनावों (आम चुनावों) की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। पाक क्रूने कहा कि चलिये बात करते हैं। मैं किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। कश्मीर का हल एक सैन्य समाधान नहीं हो सकता।

इससे पहले इमरान खान ने ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का शिलान्यास करते हुए कहा था कि उनका देश भारत के साथ 'मजबूत' और 'शिष्ट' संबंध चाहता है तथा प्रतिबद्धता के साथ दोनों देश कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं। इमरान ने कहा था, 'मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प और बड़े सपनों की जरुरत है। कल्पना कीजिए कि एक बार व्यापार शुरू हो जाता है, हमारा रिश्ते सुधर जाते हैं तो दोनों देशों को कितना फायदा हो सकता है।'

अमेरिका ने इस साल पाकिस्तान की तीन अरब डॉलर की सहायता राशि रोकी

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका ने इस साल पाकिस्तान को सुरक्षा मद में दी जाने वाली तीन अरब डॉलर की सहायता राशि को देने से टाल दिया। आतंकी समूहों पर लगाम लगाने में विफल रहने पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गयी। यह आंकड़ा पूर्व में ट्रंप सरकार द्वारा उल्लेखित 1.3 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। पीटीआई- सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभिन्न माध्यमों से किये गए भुगतान के हालिया संकलन से तीन अरब डॉलर का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। हालांकि, अब तक तीन अरब डॉलर की निलंबित राशि को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन यह इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहे गए 1.3 अरब डॉलर और पिछले सप्ताह पेंटागन द्वारा बताये गए 1.66 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। ऐसा समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच हाल में ट्विटर पर हुई जंग के बाद अमेरिकी सरकार की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस महीने कहा था कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए अमेरिका की ओर से अरबों डॉलर खर्च किये जाने के बावजूद पाकिस्तान ने उनके देश के लिए कुछ भी नहीं किया। खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें 'ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए।'

राफेल मामले में फ्रांस के दूत बोले, डील में नहीं हुआ कोई घोटाला

बेंगलुरु (एजेंसी)।

भारत में फ्रांस के दूत एलेक्जेंडर जिगलर ने बुधवार को कहा कि राफेल समझौते में कोई घोटाला नहीं हुआ। भारत और फ्रांस के बीच 'सहयोग' एवं 'विश्वास' की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लोगों से तथ्यों को ध्यान में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि क्या घोटाला? तथ्यों की ओर देखें, न कि ट्वीट पर ध्यान दें, मेरी बस यही अपील है। कथित राफेल घोटाले से भारत और फ्रांस की साझेदारी को कोई नुकसान होने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में जिगलर ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं है। फ्रेंच टेक कम्युनिटी के लॉन्च से इतर संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि पिछली उपलब्धियों को देखें, एअरोनॉटिक्स के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बने भरोसे को देखें। मेक इन इंडिया के लिए उनकी प्रतिबद्धता को देखें जो काफी प्रभावित करने वाली है। 50 प्रतिशत ऑफसेट काफी अनोखा है, बड़े सरकारी खरीद पर गौर करें।

फिलीपींस : पुलिसकर्मियों पर लगा किशोरी की हत्या का आरोप, तो कोर्ट ने सुनाई 40 साल की कैद

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

फिलीपींस में एक किशोर की हत्या के चर्चित मामले में गुरुवार को तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए. राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते द्वारा 'मादक पदार्थ के खिलाफ युद्ध' शुरू करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को अपराधी ठहराने का यह पहला मामला है.

समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलुकेन क्षेत्रीय ट्रायल कोर्ट ने अधिकारियों आर्नल ओआरेस, जेरेमियास पेरेडा और जेरविन क्रूज को अगस्त 2017 में मनीला के बाहर 17 वर्षीय किशोर कियान डेलोस सैंटोस की एक मादक पदार्थ रोधी अभियान में हत्या करने के मामले में बिना पैरोल के 40 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई और उन्हें 345,000 पेसो (6,580 डॉलर) क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का भी आदेश दिया.

अधिकारियों को हालांकि, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी नहीं पाया गया. सैंटोस के शव के बगल में 'शाबू' (एक सस्ता और बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ) के दो सैशे और एक बंदूक पाई गई थी.

फिलीपींस के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चिटो गैसकोन ने एक बयान में कहा, ÷हम कियान के हत्यारों को ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराधी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं और इस मामले में न्याय दिलाने में मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर साहसी प्रत्यक्षदर्शियों, चर्च के कर्मचारियों, मानव अधिकार रक्षकों, जांचकर्ताओं और अभियोजकों का.. जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया.÷अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि सैंटोस एक मादक पदार्थ तस्कर था लेकिन किशोर के परिवार ने इस आरोप को साफ तौर पर नकार दिया, जिसका कोई सबूत नहीं था.

जी-20 सम्मेलन : पीएम मोदी अर्जेंटीना में 50 घंटे रुकेंगे, आने-जाने में 50 घंटे खर्च होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रचार के बीच में वक्त निकाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और मालदीव गए थे. अब राजस्थान तथा तेलंगाना में होने वाले चुनावों से ऐन पहले बुधवार को वह जी20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अर्जेंटीना रवाना हुए हैं. देश में चुनाव प्रचार और विदेश में राजनयिक/कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण प्रधानमंत्री अगले कुछ दिनों में काफी लंबी यात्रा करने वाले हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी.

पीएम मोदी 23 नवंबर से ही रोजाना चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. 23 नवंबर को मिजोरम से शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने पिछले छह दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया है. बुधवार को पीएम मोदी ने सात घंटे में विमान और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर राजस्थान में दो जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया. अधिकारी ने बताया कि राजस्थान से दिल्ली पहुंचने के महज 90 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना रवाना हो गए.

दिल्ली से ब्यूनस आयर्स की यात्रा करीब 25 घंटे की है. इस दौरान 12 घंटे की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का विमान दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कुछ देर के लिए रुकेगा. प्रधानमंत्री करीब 50 घंटे अर्जेंटीना में रुकेंगे जिसके लिए वह आने-जाने पर ही करीब 50 घंटे खर्च करेंगे.

पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूनस आयर्स में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 28 नवंबर से दो दिसंबर तक अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे जिस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अन्य राष्ट्रों के नेताओं से मुलाकात करेंगे. विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि मोदी ईंधन के मूल्यों में अस्थिरता के खतरे को सबके समक्ष रखेंगे और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा धनशोधन के मुद्दों को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी.

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच यह बैठक हो रही है. गोखले ने कहा, ''हम चाहते हैं कि जी-20 में केवल व्यापार का मुद्दा नहीं छाया रहे ,चाहे यह दो देशों के बीच हो या अन्य के बीच.'' उन्होंने कहा, ''और दूसरी बात कि हम किस तरह से डब्ल्यूटीओ का सुधार कर सकते हैं जो भारत के हितों के अनुकूल हो. यह जी-20 बैठक का मुख्य मुद्दा होगा या निश्चित तौर पर जी-20 बैठक में भारत का रूख होगा.''

नई और आगामी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे: पीएम मोदी

इससे पहले ब्यूनस आयर्स में आयोजित होने वाले 13वें जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह वहां दुनिया के नेताओं से आने वाले दशक की नई एवं आगामी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. रवाना होने से पहले जारी किए गए एक बयान में मोदी ने कहा कि 10 साल के अपने अस्तित्व में जी-20 स्थिर एवं सतत वैश्विक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत रहा है.

उन्होंने कहा, 'यह लक्ष्य विकासशील देशों और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए खास तरह का महत्त्व रखता है जो आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही विशाल अर्थव्यवस्था है.÷ पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि एवं समृद्धि में देश का योगदान, ''निष्पक्ष एवं सतत विकास के लिए सर्वसम्मति बनाने' की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

उन्होंने कहा, 'मेरी इच्छा अन्य जी-20 देशों के नेताओं से मिलने की है ताकि 10 साल पहले अस्तित्व में आए जी-20 के कार्य की समीक्षा की जा सके और आने वाले दशक की नई एवं निकट आ रही चुनौतियों से निपटने के तरीके एवं साधन ढूंढने का प्रयास करेंगे.' प्रधानमंत्री ने बताया कि सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं कर प्रणालियों, कार्य का भविष्य, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना और सतत विकास पर चर्चा करेंगे.

काबुल : आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, हमले में 6 लोगों की मौत

काबुल (एजेंसी)।

ब्रिटेन स्थित एक सुरक्षा कंपनी के काबुल कार्यालय के बाहर एक दिन पहले हुये तालिबानी हमले में मरने वालों की संख्या छह हो गई है. अफगान अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. पूर्व की खबरों में 10 लागों के मारे जाने की बात कही गई थी. हालांकि अफगानिस्तान के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिद मजरोह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतकों में चार हमलावर थे. उन्होंने बताया कि 23 लोग घायल हुये हैं लेकिन किसी भी घायल की पहचान नहीं हो सकी है. एक आत्मघाती हमलावर ने बुधवार को खुद को उड़ा लिया था. उस समय सुरक्षा कंपनी ग्रुपफोरएस के नजदीक अफगान सुरक्षा बलों का चरमपंथियों के साथ संघर्ष चल रहा था. तालिबान ने कहा कि हमला दक्षिणी अफगानिस्तान में पूर्व में हुये एक अमेरिकी हवाई हमले का बदला था. हवाई हमले में 30 लोग मारे गये थे जिसमें बच्चे सहित अधिकांश असैन्य नागरिक थे. तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि हमले में मारे गये सभी 10 लोग विदेशी थे. चरमपंथी अक्सर अपने दावों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं.

कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच

दुसरे दिन भी मेगा डिमोलेशन की कार्रवाईजारी

सूरत। शहर के लाल दरवाजा क्षेत्र स्थित पटेलनगर तथा गोटालावाड़ी में गुरुार को दुसरे दिन भी डिमोलेशन जारी रहा। सुबह से शुरु हुए इस मेगा डिमोलेशन में गुरवार को देर शाम तक 150 से अधिक कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा गया।

सुबह से ही कतारगाम जोन के स्टाफ ने कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच सफलता पूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया। कतारगाम जोन के कार्यपालक इंजीनियर आर. वी. गामित ने बताया कि बुधवार से पटेल वाड़ी में डिमोलेशन की कार्रवाई जारी है। मनपा की खाली और से इस क्षेत्र में 700 से अधिक झोपड़ों को खाली करने की नोटिस दी गई थी। इससे पहले दो बार यहां के लोगों के कहने पर डिमोलेशन की कार्रवाई टाल दी गई थी। कल से कई लोगों ने स्वच्छिक रुप से मकान खाली करना शुरु कर दिया जिससे 25 से 30 मकानों का सामान हटाने में मनपा के वाहनों का सहयोग लिया गया। पहले दिन लोगों द्वारा 3 महीनों का और समय मांगकर डिमोलेशन की कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया। परन्तु पुलिस द्वारा धरपकड़ किए जाने पर लोग शांत हो गए। दुसरे दिन कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच डिमोलेशन की कार्रवाई की गई जिसमें 150 से अधिक कच्चे पक्के मकानों को डिमोलेशन कर जगह खाली कराया गया।

बेमतलब साबित हो रही है मनपा की बोर्ड समिति

लिंबायत बोर्ड समिति की बैठक में नदारत रहे अधिकारी

सूरत। नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए महागनर पालिका द्वारा रचित बोर्ड समिति की बैठक में अधिकारियों-कर्मचारियों के न आने से इसकी प्रशांगिकता पर सवाल उठने शुरु हो गए है। अधिकारियों-कर्मचारियों के रवैये से लगता है कि इस बोर्ड समिति की रचना का कोई मतलब ही नही है।

गुरुवार को मनपा के लिंबायत जोन की नई बोर्ड समिति की बैठक असलम साइकिलवाला शैलेष रायका, लीलाबने सोनवणे की उपस्थिति में आयोजित की गई है। प्रात: 11 बजे बैठक का समय होने के बावजूद लिंबायत जोन के संबधित अधिकारी और कर्मचारियों का कोई पता नहीं था। अंत में यह बैठक स्थगित करनी पड़ी। यहां गौरतलब है कि इस बोर्ड समिति के को-आर्डिनेटर असिस्टेंट कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।बावजूद इसके अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च आधिकारियों के आदेश की भी तनिक प्रभाव नहीं है।

दिव्येश दर्जी की जमानत अर्जी पर सोमवार तक टली सुनवाई

सूरत करोडों रुपएों के बिट क्वाइन की हेराफेरी के मामले में लिप्त आरोपी दिव्येश दर्जी के जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए गुरुवार को कोर्ट में अर्जी दी गई है।

सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने आरोपी दिव्येश दर्जी के अर्जी को कोर्ट से खारिज कनरे की अपलि की। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की कार्रवाई 3 दिसंबर तक के लिए टाल दी। गौरतलब है कि पिछेल महीने पूर्व टयुशन संचालक दिव्येश दर्जी ने बिटकोईन तथा बिटकनेक्ट के नाम पर लोगों को लुभावनी बातों में फंसाकर देश-विदेश में रहने वाले भोलेभाले लोगों को करोड़ों का चुना लगाया है। इस मामले में सी. आई.डी क्राइम ने आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु की। जांच में पी.आई. नरखडे ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड तक प्राप्त किया था रिमांड समाप्ति के बाद आरोपी की तरफ से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।

कडोदरा-बारडोली रोड पर मोबाइल की लूट

सूरत। कडोदरा बारडोली रोड़ से गुजर रहे एक युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उसकी जेब से मोबाइल फोन लूट लिया।

लगबघ 10 हजार रुपए कीमत की मोबाइल फोन छीनने वाले बदमाशो ंका जब युवक ने पीछा किया तो बदमाशों ने लाठी-डण्डे से युवक पर हमलाकर युवक को लहुलुहान कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का मूल निवासी तथा वर्तमान मे कडोदरा के ग्रीन सिटी में रहने वाले मुकेश कुमार संजय सिंह प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता है। 25 नवंबर की रात वह कम्पनी से घर की तरफ जा रहा था। तभी तीन बदमाशों ने उसकी जेब से मोबाइल फोन छीनना शुरु कर दिया। जब मुकेश ने मोबाइल छीन कर भाग रहे बदमाशो का पीछा किया तो बदमाशो ने लाठी-डंडों से मुकेश पर प्रहार करना शुरु कर दिया जिससे मुकेश लहुलुहान हो गया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

दक्षिण गुजरात में तापमान का पारा गिरा

शहर के उनी कपड़ा मार्केट में लगी गर्म कपड़ा खरीदने वालों की भीड़।

सूरत। उत्तर भारत में जारी शीतलहर का असर अब दक्षिण गुजरात के तापमान पर भी दिखने लगा है। जिसके चलते गुरुवार ोक तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। सुबह-सुबह गुलाबी ठण्डी के साथ लोगों को सर्दी की अनुभूति हुई। इसबात से अब लगने लगा है कि सर्दी ने दस्तक दे दी है।

मानसून विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.2 डीग्री तथा न्यूनतम तापमान 18.5 डीग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा 5 प्रतिशत तथा हवा का दबाव 1017.2 मिलीबार दर्ज किया गया। शहर में सुबह से उत्तर दिशा की तरफ से 5 किमी प्रति घंटे की वेग से हवाएं चली। उत्तर दिशा की और से आने वाली हवाओं के चलते बुधवार की तुलना में गुरुवार का तापमान 1 डीग्री कम रहा।

पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में रोड़ सेफ्टी काउंसिल की बैठक

सूरत। सूरत शहर रोड़ सेफ्टी एण्ड काउंसिल की बैठक गुरुवार को पलिस कमिश्नर सतीष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अमरौली चार रास्ता पर सुबह लथा शाम को होने वाले ट्राफिक जाम की समस्या को लेकर चर्चा हुई। जिसमें डायमंड कलाकारों तथा औधोगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगरों के छुटने के समय में आधे घंटे का अंतराल रखने को कहा गया। इसके आलावा डुमस बीच सुरक्षा को ध्याम में रखते हुए सभी सर्कलों की नियमित मरम्मत को ध्यान देने पर जोर दिया गया। साथ ही शहर में बढती ट्राफिक की समस्या से निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा किया गया।

किराएदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत

सूरत। अडाजन के वेस्टर्न सोमचिंतामणि रेसीडेंसी का फ्लैट बेचने के बाद उस फ्लैट में किराए पर रहने वाले पूर्व फ्लैट मालिक के खिलाफ नये फ्लैट मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

अडाजन पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू सिटीलाइट के चाइना बोर्ड के पीछे आर्शिवाद एन्कलेव में रहने वाली संगीताबेन मितुल कुमार छुछा ने आरोपी बाबूलात माघोजीभाई अदाणी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। संगिताबेन ने पुलिस को दिए अपने शिकायत में बताया है कि अडाजन के वेस्टर्न सोमचिंतामणि रेसीडेंसी स्थिति फ्लैट नं. डी/201 को 21.72 लाख रुपये में खरीदा था। जिसका भुगतान चैक द्वारा किया था। मकान बेचने के बाद आरोपी बाबूलाल माघोजी भाई अदाणी ने संगीता बेन से बेचे गए फ्लैट को किराए पर रहने के लिए ले लिया। आरोपी ने फरीयादी के पति से 28.28 लाख रुपये उधार लिया था। जिसे न तो वह वापस कर रहा है और न ही फ्लैट खाली कर रहा है।

महिला के हाथ से नगद 51 हजार भरा पर्स छीनी

सूरत। शहर के रिंग रोड कमेला दरवाजा निकट चालू बाइक पर महिला के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों के अनुसार भटार ब्रेडलाइनर सर्कल निकट गिरधर द्वार सोसायटी निवासी अवनिशभाई गत 16 नव बर को सुबह पांच बजे अपने गांव पाटण से बस में बैठकर आई पत्नी निशाबेन को बस स्टेशन के पास से लेकर बाइक पर घर आ रहे थे। तभी रिंग रोड कमेला दरवाजा के पास बाइक पर आए दो अज्ञातों ने अवनिश की पत्नी निशाबेन के हाथ से पर्स झपट लिया और उधना दरवाजा की तरफ भाग गए। निशाबेन के पर्स में नगद 51 हजार था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

महाराष्ट्र की पेटर्न पर सरकार आरक्षण मुद्दे पर विचार करेगी

अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठियों को आरक्षण देने की घोषणा करने के बाद गुरुवार को १६ फीसदी आरक्षण देने का बिल पारित करने से पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है अब गुजरात में भी भाजपा की सरकार होने से महाराष्ट्र सरकार की पेटर्न पर गुजरात सरकार भी पाटीदारों को आरक्षण मामले में आगे बढ़े ऐसी संभावना रही है। हालांकि, इसके पहले ओबीसी आयोग सरकार के अभिप्राय के आधार पर सर्वे करायेगी और इस मामले में अब किस डेवलपमेन्ट की संभावना बनी हुई है।

दूसरी तरफ, पाटीदार प्रदर्शनकारी नेताओं ने भी गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के मराठियों को आरक्षण देता बिल की घोषणा करने के बाद गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया और भाजपा सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति से यह मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर लागू करने के लिए अनुरोध किया गया है। पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए युवा आंदोलन कर रहे है। ऐसे समय में महाराष्ट्र में मराठियों को १६ फीसदी आरक्षण देने का बिल को सरकार को मंजूरी दी है। अब गुजरात सरकार भी पाटीदारों को आरक्षण देने के मामले में जल्दी से प्रक्रिया शुरू करे ऐसी संभावना है।

इस दौरान सुज्ञाबहन भट्ट की ओबीसी आयोग के समक्ष गुरुवार को पास की कॉर कमिटी के अग्रणी फिर से आरक्षण मामले में पेशकश करने पहुंचे थे और अपने मुद्दे की फिर से पेशकश करके जल्दी से सर्वे कराने का अनुरोध किया गया। जिसकी वजह से अब आयोग द्वारा गुजरात सरकार के पास अभिप्राय मांगा जाएगा। सरकार के अभिप्राय के आधार पर ओबीसी आयोग द्वारा गुजरात राज्य में पाटीदार जाति का सर्वे शुरू किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया संभव होगी।

उनाकांड के ११ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने आरोपियों को ५४,५०० का जुर्माना लगाया फैसले की वजह से दलित समाज में खुशी फैल गई

अहमदाबाद । गीर सोमनाथ जिला की उना तहसील के आंकोलाली गांव के दलित युवक को २०१२ में जिंदा जलाकर अत्याचार किए जाने से केस में ११ आरोपियों को गुरुवार को उना सेशन्स कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिसकी वजह से दलित समाज में न्याय मिलने की खुशी फैल गई। उना सेशन्स कोर्ट के फैसले को लेकर राज्यभर के दलित समाज में इसकी काफी चर्चा हो रही है और ११ आरोपियों को जीवित रहे तब तक आजीवन कारावास की सजा का आदेश चर्चा का केन्द्र बन गया।

उना के एडिशनल सेशन्स न्यायाधीश एसएल. ठक्कर ने जिस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई यह आरोपियों में भाणा काना, बाबु दाना, धीरू वीरा, भीखा वीरा, राम भीखा, पांचा लाखा, प्रवीण धीरू, हमीर अरजण, अरजण बाबू, गभरू काना और लालजी वशराम शामिल है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को ५४,५०० रुपये का जुर्माना लगाया गया है इतना ही नहीं सभी आरोपियों का मिलाकर कुल ५,९९,५०० रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह पूरे केस को रेरेस्ट ऑफ ध रेर बताकर सभी आरोपी जीवित रहेंगे तब तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस बारे में यह जानकारी है कि, गत १३.९.२००२ को लालजीभाई सरवैया नाम के दलित युवक को गांव के एक समुदाय के लोगों ने मिलकर घर में जिंदा जला दिया था। इतना ही नहीं इसके परिवार के बाकी सदस्यों को भी सामूहिक हमला करके इसकी पिटाई की गई थी। यह पूरे मामले में गीर गढडा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-३०२ और एट्रोसीटी एक्ट की धारा ३(२) ५ के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस घटना की वजह से राज्यभर में सनसनी मच गई और उनाकांड की प्रतिक्रिया देशभर में हुई थी। बाद में विवाद बढ़ने से राज्य सरकार ने २०१५ में शिकार होने वाले परिवार को विस्थापित घोषित करके उनको खेती के लिए ५.३३ एकड़ जमीन आवंटन कराई गई थी। इस केस में पीड़ित परिवार और शिकायतपक्ष की तरफ से वकील मनोज श्रीमाली, भानुभाई शेखावा ने महत्वपूर्ण दलीलें देकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई थी। शिकायतपक्ष की दलीलें मान्य रखकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी और एट्रोसीटी ऐक्ट के प्रावधान के तहत दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)